



F.R. 20/

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डलाधारियर केम्प, सागर म.पु.

तिथि - 16- II - 16

रामवती पत्ति मूलधंद उर्फ मुनुआ अहिरवार

निवासी ग्राम टौरियातड़ पोरा जिला टीकमगढ़ म.पु.

• निगरानी कर्ता/आवेदक

// विल्ह //

1. राष्ट्रीय तथा पंचा अहिरवार

निवासी ग्राम टौरियातड़ पोरा जिला टीकमगढ़ म.पु.

• अवेदक

विवरणी अंतर्गत धारा 50 म.पु. भू. रा. तंदिता 1959.

निगरानी विल्ह आदेश श्रीमान् अपरआयुष्म तांग संभाग, सागर

के प्र.पु. 6113/12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2015

से परिवेदित होकर प्रस्तुत ।

महोदय,

निगरानी कर्ता की ओरसे निम्न प्रार्थना है -

यहाँकि संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि

भूमि क्र.नं. 2/12 रक्ता 2.00 हेक्टेयर निगरानी कर्ता के द्वारा

भूमि तेजुंहर बेबा मंगल सिंह से रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा ख्रप की थी।

जिसका नामांतरण पंजी क्रमांक 17 दिनांक 23.03.2007 के द्वारा

ग्राम टौरिया ऊङ्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था। जिसके आधार

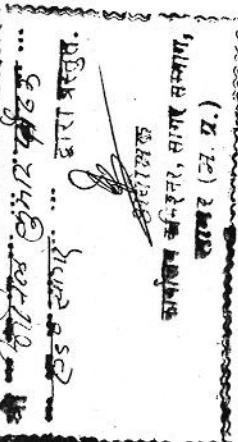
पर निगरानी कर्ता द्वारा ज्ञापन भूमि पर कब्जा प्रा एत किया

गया ।

यहाँकि विक्रेता तेजुंहर एवं मंगलसिंह के सीमांकन

1102-20.

2:-



No. 1
28.1.16
Ran

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 16—दो/16

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	शास्त्री	कार्यवाही तथा आदेश (ग्रन्थ)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-2016			
		यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 61/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 24-9-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।	
		2/ निगराकार अधिवक्ता ने तर्क में कहा कि निगराकार ने वाद भूमि तेजकुंवर से खरीदी थी जिसका नामांतरण पंजी क्रमांक 17 पर दिनांक 23-3-07 को हुआ था, एवं तहसीलदार ने दिनांक 7-6-08 को सीमाकंन स्वीकृत किया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में अपर कलेक्टर ने सीमांकन को यथावत रखा, जिससे सीमाकंन अंतिम हो गया, जिसमें निगराकार की 0.800 हैक्टेयर भूमि पर गैर निगराकार का कब्जा पाया गया है।	
		3/ इसके आधार पर निगराकार ने धारा 250 में बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ कराई जिसमें दिनांक 15-6-09 को कब्जा हटाने का आदेश हुआ और अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 14-7-09 को सिविल जेल का आदेश किया।	
		4/ तहसीलदार के आदेश दिनांक 15-6-09 के विरुद्ध गैर निगराकार ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी की थी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-9-09 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को स्वत्व के बिन्दु पर साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित कर दिया।	
		5/ इसके विरुद्ध निगराकार द्वारा अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष की गई निगरानियों के आदेशों से निगराकार	

A

M

संतुष्ट नहीं हुआ, और अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में आया है।

6/ अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 24-9-15 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने अपने आदेश के अंतिम पैरा में यह बिल्कुल स्पष्टतः लिखा है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना क्यों सही है। इसमें उन्होंने लिखा है कि तेजकुंवर को दखल रहित अधिनियम 1984 के अंतर्गत कब्जा दिया जाना नहीं पाया जाता, और भूमिस्वामी स्वत्व विवादित है, जिसकी वजह से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तन किया जाना उपयुक्त है।

7/ आवेदक अधिवक्ता ने तर्क में कहा है कि दखलरहित अधिनियम 1984 के तहत अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने की अधिकारिता नहीं थी, किन्तु उन्होंने अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि “तेजकुंवर को दखल रहित अधिनियम के अंतर्गत कब्जा दिया जाना नहीं पाया जाता” का ना तो तर्क या मेमों में खण्डन किया है और ना ही उसके खण्डन के कोई आधार बताए हैं। ऐसे में अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष को गलत मानने का और अनुविभागीय अधिकारी को अधिकारिता नहीं होने का बिन्दु शेष नहीं रहता।

8/ आवेदक का यह तर्क कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने ही सिविल जेल के आदेश के बावजूद उनका आदेश दिनांक 30-9-09 का आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने एक अन्य प्रकरण में पारित किया है और इस आदेश से संबंधित प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्वत्व के बिन्दु पर पुनः विचार कराए जाने की आवश्यकता आई, जिस वजह से उन्होंने अपना आदेश किया।

निगो 16-दो/16
रामायणी

२१८५६

जिला टीकमगढ़

- 9/ वैसे भी अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश से अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तन आदेश यथावत रहा है, जिसके फलस्वरूप आवेदक सहित उभयपक्ष के पास विचारण न्यायालय के समक्ष पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है।
- 10/ उपरोक्त के प्रकाश में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य

M